



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



4 प्रवासी राजस्थानी समुदाय ने राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गौरवान्वित

6 भारत के सशक्त स्वास्थ्य मोर्चे का दुनिया ने लोहा माना

7 किसी घुसपैटिए के लिए भारत 'खाला' का घर नहीं : कैथव प्रसाद मोर्य

फ़र्स्ट टेक

किसानों को डीएपी की बोरी 1350 रुपए में मिलेगी नई दिल्ली/एजेन्सी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने डीएपी की कीमत 1350 रुपए प्रति बोरी तय की है ताकि किसानों को अधिक कीमत नहीं देनी पड़े इसके लिए भारी सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। चौहान ने यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फॉरफेटिक और पोटासिक (पीएडके) उर्वरकों पर खरीफ सीजन, 2025 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल भी लगभग एक लाख 75 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को सरती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने दी है। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 13,000 करोड़ रुपए अधिक है।

वायु सेना और सेना को मिलेंगे 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर नई दिल्ली/एजेन्सी। रक्षा मंत्रालय ने वायु सेना और सेना के लिए 156 हल्के लड़ाकू हेलिकॉप्टर प्रचंड की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ 62,700 करोड़ रुपए के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल 156 हेलीकॉप्टर में से 66 हेलिकॉप्टर भारतीय वायु सेना को और 90 की भारतीय सेना को आपूर्ति की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि अनुबंध में प्रशिक्षण और अन्य संबद्ध उपकरण भी शामिल हैं।

कठुआ मुठभेड़ के दूसरे दिन तीन पुलिसकर्मियों के शव बरामद

जम्मू/भाषा। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू-कश्मीर के चार पुलिसकर्मियों में से तीन के शव शुक्रवार को बरामद कर लिए गए जबकि जम्मू के कठुआ के सुदूर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण गोलीबारी दूसरे दिन भी जारी है। अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हालांकि, मृतक कर्मियों के सर्विस हथियार अब भी लापता हैं। राजबाग के घाटी जूथाना क्षेत्र में जखोले गांव के निकट केंद्रित यह अभियान हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से हाल ही में घुसपैट करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस अभियान के बाद बृहस्पतिवार सुबह शुरू हुआ। मुठभेड़ में चार पुलिसकर्मियों शहीद हो गए जबकि जैश के तीन आतंकवादी डेर हो गए। मुठभेड़ में एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) समेत सात अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह ज़ोन की मदद से खोजी दलों को चौथे पुलिस कर्मी के शव का पता चला।

28-03-2025 29-03-2025
सूर्योदय 6:31 बजे सूर्यास्त 6:17 बजे

BSE 77,414.92 NSE 23,519.35
(-191.51) (-72.60)

सोना 9,244 रु. चांदी 100,300 रु.
(24 केर) प्रति बाम प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका
epaper.dakshinbharat.com

आत्मनिर्भर बनें
सुदृढ़ हो सारा अर्थतंत्र, अपनी क्षमताओं को तोले। अपने पुरुषार्थ पसीने से, रुजगार बढ़े हौले-हौले। भारत सक्षम होये समर्थ, भारतवासी निज पर खोले। हम रहें परंपर मिल कर के, ना वैमनस्य हरगिज घोले।।

‘संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा वक्फ विधेयक’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। इस विधेयक को अप्रैल 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। मौजूदा बजट सत्र के चार अग्रलेख को समाप्त होने में केवल चार कार्य दिवस शेष रह गये हैं। शाह ने 'टाइम्स नाउ समिट 2025' में कहा, "हम इसी सत्र में संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे।" उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए क्योंकि नरेन्द्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। उन्होंने कहा, "विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। वे सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं।"

विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। वे सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार को मौजूदा कानून में संशोधन विधेयक लाना पड़ा क्योंकि मूल कानून तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वक्फ अधिनियम में ऐसे नियम बनाए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा, हमने वक्फ विधेयक को संविधान के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को तोड़-मरोड़ कर पेश किया था। शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 123 प्रमुख स्थानों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है और प्रयागराज में ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला भोजन बिल पर सेवा शुल्क स्वैच्छिक है, रेस्तरां इसे अनिवार्य नहीं बना सकते

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि भोजन के बिल पर ग्राहकों द्वारा सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना स्वैच्छिक है और इसे रेस्तरां अनिवार्य नहीं बना सकते। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह फैसला सुनाया और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के उन दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्तरां निकायों की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें होटल एवं रेस्तरां पर भोजन बिल पर अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क वसूलने को लेकर रोक लगाई गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि भोजन बिल पर अनिवार्य रूप से सेवा शुल्क लेना 'भ्रामक' और 'धोखाधड़ी' है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को यह आभास होता है कि यह सेवा कर या

भोजन के बिल पर सेवा शुल्क की अनिवार्य वसूली उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन और कानून के विपरीत है।

जीएसटी के रूप में लगाया जा रहा है। न्यायमूर्ति सिंह ने इसे अनुचित व्यापार पद्धति करार दिया और कहा कि इसे अनिवार्य रूप से बिल में नहीं जोड़ा जा सकता। 'फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई)' और 'नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई)' ने 2022 में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया था।

आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को उसके गढ़ चेपाँक पर हराया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। कप्तान रजत पाटीदार के अर्धशतक और गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु ने 17 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स को उसके गढ़ चेपाँक पर आईपीएल के मैच में मात देते हुए शुक्रवार को 50 रन से जीत दर्ज की। आरसीबी के सात विकेट पर 196 रन के जवाब में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आठ विकेट पर 146 रन ही बना सकी। आरसीबी की 2008 में आईपीएल के पहले सत्र के बाद चेपाँक पर चेन्नई के खिलाफ यह पहली जीत है। पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर मजबूत स्कोर बनाने के बाद आरसीबी ने मेजबान टीम के



शुरुआती विकेट जल्दी चटकाकर दबाव बनाया जो अंत तक कायम रहा। चेन्नई के बल्लेबाज अपनी गलतियों से विकेट गंवाते चले गए जबकि क्षेत्ररक्षण में भी मेजबान टीम ने निराश किया। चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही और कप्तान रूतुराज गायकवाड़ खाता भी नहीं खोल सके। चेन्नई ने पहले दो ओवर में ही तीन विकेट गंवा दिये। दूसरे ओवर में राहुल त्रिपाठी (पांच) ने जोश हेजलवुड को पूल शॉट खेलने के प्रयास में शॉर्ट मिडविकेट पर कैच थमाया। हेजलवुड ने 21 रन देकर तीन विकेट लिये। दीपक हुड्डा ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमाया। उस समय चेन्नई का स्कोर तीन विकेट पर आठ रन था।

गठबंधन पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उचित फैसला लेगा : अन्नमलार्ई

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के. अन्नमलार्ई ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कवगम (द्रमुक) को हटाने के लिए राज्य विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा के साथ आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कवगम (अन्नाद्रमुक) के फिर से गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। अन्नाद्रमुक के महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यहां उनके आवास पर मुलाकात की थी।

नेपाल में राजशाही की मांग हुई तेज

राजशाही समर्थकों की पुलिस से झड़प में दो लोगों की मौत, पूर्वी काठमांडू में सेना बुलाई गई

इजराइल ने फिर किया बेरुत पर हमला

बेरुत/एपी। इजराइल-हिजबुल्ला के बीच नवंबर में हुए युद्ध विराम के बाद इजराइल ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरुत पर पहली बार हमला किया। बेरुत में बड़ा धमाका सुना गया और उस क्षेत्र से धुएँ का गुबार उठता दिखाई दिया, जहां इजराइल की सेना ने हमला किया। यह हमला पिछले साल 27 नवंबर 2024 को इजराइल और हिजबुल्ला उग्रवादी समूह के बीच युद्ध विराम होने के बाद बेरुत पर पहला हमला था, हालांकि इजराइल ने तब से लगभग रोजाना दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया। इजराइली सेना ने कहा कि उसने दहियाह के इलाके में हिजबुल्ला के 'ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी' पर हमला किया, जिसे उसने हिजबुल्ला का एक अहम गढ़ बताया। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्ला नागरिकों को मानव बाल के रूप में इस्तेमाल करता है और उसने लोगों को वहां से चले जाने की पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

काठमांडू/भाषा। नेपाल में राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा राजनीतिक दल के कार्यालय पर पथराव और हमला किए जाने से दो लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोगों के घायल होने के बाद शुक्रवार को सेना को बुलाया गया और काठमांडू के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने पहले शाम 4:25 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया था, बाद में इसे शनिवार सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया। कुछ इलाकों में किसी को भी घूमने-फिरने की अनुमति नहीं दी गई।



गई। अधिकारियों ने बताया कि झड़प के दौरान गोली लगने से काठमांडू के 29 वर्षीय सबिन महाराजन की अस्पताल में मौत हो गई। तिनकुने क्षेत्र में एक इमारत से विरोध प्रदर्शन का वीडियो शूट करते समय एग्ज्यूटिव टेलीविजन के फोटो पत्रकार सुरेश रजक की मृत्यु हो गई। यह वह स्थान है जहां राजतंत्रवादियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प की थी और सुरक्षा अवरोधकों को तोड़ने का प्रयास किया था। एग्ज्यूटिव टीवी के एक सूत्र के अनुसार, आग लगने के तुरंत बाद रजक लापता हो गए थे। बाद में, पुलिस को इमारत की चौथी मंजिल पर बुरी तरह से जला हुआ शव मिला, जिसके बारे में संदेह है कि वह रजक का है।

हजारों राजतंत्रवादियों ने नेपाल में राजतंत्र की बहाली की मांग करते हुए राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजतंत्र वापस चाहिए जैसे नारे लगाए।

प्रधानमंत्री के. पी. ओली ने देश में व्याप्त अशांति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शनकारी आर्मी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

एग्ज्यूटिव टीवी के एक सूत्र के अनुसार, आग लगने के तुरंत बाद रजक लापता हो गए थे। बाद में, पुलिस को इमारत की चौथी मंजिल पर बुरी तरह से जला हुआ शव मिला, जिसके बारे में संदेह है कि वह रजक का है। अधिकारिक पहचान अभी नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से लगभग आधे पुलिसकर्मी थे। झड़प के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने एक घर को जला दिया।

थाईलैंड और म्यांमार में शक्तिशाली भूकंप, 150 से अधिक लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बैंकाक/एपी। म्यांमार और पड़ोसी देश थाईलैंड में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से इमारतें, एक पुल और एक बांध नष्ट हो गया। म्यांमार में कम से कम 144 लोगों की मौत हुई है। यहां के दो सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों से ली गई तस्वीरों और वीडियो में भारी नुकसान दिख रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के ढह जाने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई।



शुक्रवार दोपहर आए भूकंप की तीव्रता 7.7 दर्ज की गई और इसका केन्द्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट था। इसके बाद 6.4 तीव्रता का एक और शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेर्रेस ने कहा कि विश्व निकाय म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। भूकंप से मौतों, हताहतों और विनाश को लेकर पूरी तस्वीर अबतक स्पष्ट नहीं है, खास तौर पर म्यांमार में, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यह गृहयुद्ध में चल रहा है और यहां सूचना पर कड़ा नियंत्रण है। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख ने शुक्रवार शाम को टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि भूकंप संबंधी घटनाओं में कम से कम 144 लोग मारे गए और 730 अन्य घायल हुए। वरिष्ठ जनरल निन आंग हाइंग ने कहा, "मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है।" राजधानी नेपीता से प्राप्त तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि भूकंप के कारण सरकारी

शुक्रवार दोपहर आए भूकंप की तीव्रता 7.7 दर्ज की गई और इसका केन्द्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के निकट था।

कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तथा बचाव दल मलबे से पीड़ितों को निकाल रहे हैं। म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में खून की बहुत अधिक जरूरत है। मांडले में टूटी-फूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त राजमार्गों के साथ-साथ पुल और बांध के ढहने की तस्वीरें इस बात को लेकर और भी चिंता पैदा करती हैं कि बचाव दल पहले से ही व्यापक मानवीय संकट से जूझ रहे देश के कुछ इलाकों तक कैसे पहुंच पाएंगे। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बैंकाक के चतुर्थक बाजार के पास एक निर्माणाधीन 33 मंजिला इमारत, जिसके ऊपर एक क्रैन रखी हुई थी, धूल के गुबार में तब्दील हो गई। भूकंप के तुरंत बाद अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। चेतावनी सायरन की आवाज पूरे मध्य बैंकाक में गूंज उठी।



सीखने से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है : राज्यपाल गहलोत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। छात्रों को न केवल शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए बल्कि अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए। हमारे पास जो ज्ञान है उसे कोई नहीं चुरा सकता। अगर हम ज्ञान प्राप्त करने तो सफलता की राह आसान हो जाएगी, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने छात्रों का आह्वान करते हुए कहा। वह शहर के सीएमआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ़टेरिअरिज्मेंट के नवोदघाटन समारोह में भाग लेते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, जीवन की सफलता में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है, शिक्षित होने पर ही व्यक्ति का विकास हो सकता है। शिक्षा हमें तकनीकी और उच्च कोशल वाला ज्ञान और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा कौशल को बढ़ाती है और कौशल से हम जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उसमें बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली बहुत समृद्ध और विशाल थी, इसलिए हमें विशुद्ध माना जाता था और हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए हमें अपने युवाओं के कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा का प्रदर्शन करके ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है और इसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, शिक्षित युवा समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। युवा चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं - चाहे वह विज्ञान,

तकनीक, व्यवसाय, कला या समाज सेवा हो, देश उनके प्रयासों से ही आगे बढ़ता है। आज का युवा नवाचार और प्रतिस्पर्धा का युग है। वर्तमान डिजिटल युग वह है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा साइंस और उन्नत प्रौद्योगिकियां दुनिया को नए आयाम दे रही हैं। सीखने के साथ-साथ हमें नवाचार और रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक सफल व्यक्ति वह है जो बदलते समय के साथ तालमेल बिठाता है, नई चीजें सीखता है और नेतृत्व कौशल विकसित करता है।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से देश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था आज विश्व में एक गंभीर समस्या है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जल, जंगल और वायु संरक्षण के लिए और अधिक काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनें और एक भारत-श्रेष्ठ भारत तथा स्वतंत्रता के निर्माण में भागीदार बनें। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। स्वामी विवेकानंद कहते थे - उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए एक समय में एक ही काम करो और उसे पूरी निष्ठा से करो। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवा शक्ति ही राष्ट्र के विकास का आधार है। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भरता, साहस और आत्मविश्वास की प्रेरणा दी। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए।

उन्होंने कहा, शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ हमें नैतिकता, कठ्ठना और सामाजिक जिम्मेदारी भी भावना भी देती है। शिक्षा एक सतत यात्रा है जो व्यक्ति के जीवन में नए विचार, ज्ञान और संभावनाएं भरती है। बेंगलूरु शहर देश के कई विश्वस्तरीय शैक्षणिक और शोध संस्थानों का घर है। इस कारण से, बेंगलूरु को शिक्षा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। सीएमआर ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स ने बेंगलूरु को शिक्षा केंद्र बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। यह सराहनीय है कि 2013 में स्थापित सीएमआर विश्वविद्यालय ने कम समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। हंस की नाजूक चोंच में भेदभाव की शक्ति होती है और कहा जाता है कि दूध और पानी के मिश्रण में शुद्ध दूध और पानी के बीच अंतर करने की क्षमता होती है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सीएमआर विश्वविद्यालय निरंतर और सकारात्मक सक्रिय प्रयास करके विकसित भारत के लिए मानव संसाधन को प्रभावी बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, राज्यपाल ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा, यह प्रसन्नता की बात है कि समाज, जनहित और देशहित में कार्य करने वाले बौद्धिक प्रभु और श्रीकांत को दीक्षांत समारोह में मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया। मैं उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि समाज और देश की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान जारी रहेगा। सीएमआर ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के चेयरमैन डॉ. के.सी. राममूर्ति और डॉ. सविता राममूर्ति उपस्थित थे।

केवल कविता पाठ या स्टैंड-अप कॉमेडी से नफरत नहीं फैल सकती: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली/भाषा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए पुलिस की कड़ी निंदा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि महज कविता, स्टैंड-अप कॉमेडी और कला या मनोरंजन के किसी भी रूप के प्रदर्शन से समुदायों के बीच दुश्मनी या घृणा पैदा होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ प्राथमिकी को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति

उज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि कविता, नाटक, फिल्म, स्टैंड-अप कॉमेडी, व्यंग्य और अन्य 'स्टेज शो' सहित साहित्य में मानव जीवन को अधिक सार्थक बनाया है। पीठ ने कहा, हमारे गणतंत्र के 75 वर्षों के बाद भी हम अपने मूल सिद्धांतों के मामले में इतने कमजोर नहीं दिख सकते कि महज एक कविता या किसी भी प्रकार की कला या मनोरंजन जैसे स्टैंड-अप कॉमेडी के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी या घृणा

पैदा करने का आरोप लगाया जा सके। अदालत ने आगे कहा, ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने से सार्वजनिक क्षेत्र में सभी वैध विचारों की अभिव्यक्ति बाधित होगी, जो स्वतंत्र समाज के लिए बहुत ही मूलभूत चीज है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि हमारे संविधान के अस्तित्व में आने के 75 साल बाद भी राज्य की कानून प्रवर्तन प्रणाली इस महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के बारे में या तो अनभिज्ञ है या

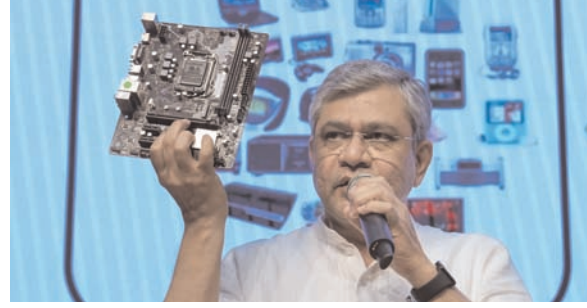
इसकी परवाह नहीं करती। कांग्रेस नेता ने गुजरात उच्च न्यायालय के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। प्रतापगढ़ी पर तीन जनवरी को जामनागर में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान कथित भड़काऊ गीत गाने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

फॉस्फेट, पोटाश उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस साल खरीफ (ग्रीष्मकालीन) सत्र के लिए फॉस्फेट एवं पोटाश (पीएंडके) आधारित उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने को मंजूरी दी। सरकार की तरफ से दी जाने वाली यह सब्सिडी उचित दर पर मृदा को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के प्रयासों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल

की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि फॉस्फेट एवं पोटाश (पीएंडके) आधारित उर्वरकों पर खरीफ सत्र 2025 (एक अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस कदम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की खुदरा कीमतें वर्तमान स्तर पर बनी रहें। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल



के इस निर्णय से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, उर्वरकों और

कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझान को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी की व्यवस्था एनबीएस योजना के तहत संचालित होती है।

उर्वरकों पर सब्सिडी खरीफ सत्र 2025 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर दी जाएगी। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित एवं अधिसूचित दरों के अनुरूप सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को किफायती कीमतों पर पोषक तत्व उपलब्ध कराए जा सकें। केंद्र सरकार पोषक तत्वों के निर्माताओं/आयातकों के जरिये किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 28 शेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। अप्रैल 2010 से पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी की व्यवस्था एनबीएस योजना के तहत संचालित होती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी। यह निर्णय इस साल एक जनवरी से लागू होगा। इससे करीब 1.15 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। दो प्रतिशत वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 53% से 55% हो गया है। इसका मकसद महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है। डीए और डीआर दोनों में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,614.04 करोड़ रुपए का असर होगा। इस कदम से केंद्र सरकार के करीब 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सालवत् केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। डीए तथा डीआर का भुगतान जीवन-यापन की लागत को समायोजित करने और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा क्षेत्र के लिए 23 हजार करोड़ रुपए की पीएलआई योजना मंजूर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 22,919 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ गैर-सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 91,600 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा जबकि लाभ 59,350 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने का अनुमान

है। सरकार की यह पहली योजना है जो निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। निष्क्रिय यानी गैर-सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्ज बिजली को नियंत्रित करने के लिए जरूरी उपकरण होते हैं लेकिन वे खुद बिजली का उत्पादन या उसमें बदोतरी नहीं करते हैं। वैष्णव ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक पीएलआई योजना के तहत निष्क्रिय घटकों को मंजूरी दी गई है। इसका कुल पैकेज 22,919 करोड़ रुपए का है। यह छह साल में पूरा होगा। यह खंड दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, चिकित्सा उपकरण, बिजली क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा। मंत्री ने कहा कि इस योजना से 4.56 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन होने की उम्मीद है।

'कुंभ में रेलगाड़ियों के शीशे तोड़ने की 23 घटनाओं में रेलवे को 3.3 लाख का नुकसान'

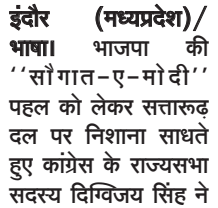
नई दिल्ली/भाषा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सवारी डिब्बों के दरवाजे व खिड़कियों के शीशे तोड़ने की 23 घटनाएं हुईं और इनमें रेलवे को 3.3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित सवाल के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इन घटनाओं में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से की गई कानूनी कार्रवाई में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। द्रविड़ मुन्नेत्र कश्मम की सदस्य एम वी एम सोमू ने रेल मंत्री से कुंभ मेले के दौरान रेलवे संपत्ति को हुए नुकसान का ब्योरा मांगा था। वैष्णव ने इसके जवाब में कहा, "कुंभ मेले के दौरान विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सवारी डिब्बों के दरवाजे या खिड़कियों के शीशे तोड़ने की 23 घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है।" उन्होंने कहा, "इन घटनाओं में रेलवे को लगभग 3.3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सभी घटनाओं में रेल सुरक्षा बल द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई, जिनमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया।"

दिल्ली की भाजपा सरकार को संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये कानून बनायेगी : सूद



नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह शहर में आवागमन के लिए एक कानून बनाएगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में आवागमन एवं अर्थ जनसंचयन के मुद्दे पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। सूद ने कहा, "हम उचित विचार-विमर्श के बाद जो संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक कानून लाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार के विभिन्न विभागों के बीच कोई गलतफहमी न हो और हम कानून के लिए भारतीय न्याय संहिता (सीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं का अध्ययन करेंगे।"

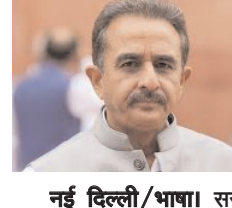
"सौगात-ए-मोदी" को लेकर दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा



इंदौर (मध्यप्रदेश)/भाषा। भाजपा की 'सौगात-ए-मोदी' पहल को लेकर सतारूद दल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मुसलमानों को तोहफे दिए जाना अच्छी बात है, लेकिन उनके घर नहीं तोड़े जाने चाहिए और सांस्कृतिक सद्भाव का माहौल तैयार किया जाना चाहिए। सिंह ने इंदौर में 'सौगात-ए-मोदी' के बारे में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा, "अच्छा है कि वे (भाजपा) मुस्लिमों को सौगातें दें, लेकिन कम से कम उनके घर तो न तोड़ें और उनके घरों को बर्बाद तो न

करें।" जो लोग मुसलमानों को तोहफे बांट रहे हैं, वे उन्हें कम से कम इतना ही तोहफा दें कि उनके खिलाफ अनर्गल बलों न करें। वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव का माहौल तैयार करें और मंदिर-मस्जिद की लड़ाई न करें।" उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद न्यायिक जवाबदेही की बहस तेज होने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, "यह जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। अगर किसी और व्यक्ति के घर में इतनी नकदी मिली होती, तो अब तक वह व्यक्ति जेल में होता।"

वन्य जीव कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं : सरकार



नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने संसद को सूचित किया है कि वर्तमान में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। माकपा सदस्य श्री शिवदासन के एक सवाल के लिखित जवाब में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री शिववर्धन सिंह ने राज्यसभा को यह जानकारी दी। मंत्री सिंह ने कहा, "मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन सहित वन्यजीवों का संरक्षण मुख्य रूप से संबंधित राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है।" उन्होंने कहा कि कानून की धारा 11 (1) (क) राज्य के मुख्य

वन्यजीव वार्डन को अनुसूची एक में आने वाले उन जानवरों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देती है, जो मानव जीवन के लिए खतरा बन जाते हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन या किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को अनुसूची-दो के अंतर्गत आने वाले ऐसे जानवरों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देती है, जो जानवर मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा बन गए हैं। माकपा सदस्य ने सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार जंगली जानवरों के हमलों से निपटने में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का इरादा रखती है? इसके जवाब में मंत्री ने कहा, "वर्तमान में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।"

हवाई अड्डों पर निशुल्क पेयजल के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए : बिरला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से कहा कि वह हवाई अड्डों पर वाटर कूलर की व्यवस्था करें, ताकि यात्रियों को निशुल्क पेयजल उपलब्ध हो सके। सदन में गैर-सरकारी कामकाज के तहत कांग्रेस सांसद शफी परन्विल के 'देश में हवाई यात्रा किराये के विनियमन के लिए उचित उपाय' संबंधी निजी संकल्प पर चर्चा के दौरान बिरला ने यह टिप्पणी की। चर्चा के दौरान, आजाद समाज पार्टी (काशीराम) के सांसद चंद्रशेखर ने हवाई अड्डों पर पानी की बोतल अत्याधिक कीमतों पर उपलब्ध होने का उल्लेख किया। इस पर बिरला ने कहा, "मंत्री जी, वाटर कूलर लगावा दो ताकि निशुल्क पानी मिले। जरूरी नहीं है कि सभी लोग बोतल का ही पानी पियें।" नायडू ने कहा कि कुछ हवाई अड्डों पर 'उड़ान यात्री' सुविधा शुरू की गई है जिसके तहत 10 रुपए में पानी की बोतल उपलब्ध कराई जा रही है।



लुटियन्स दिल्ली में मुगलों के नाम वाले साइनबोर्ड विरूपित

नई दिल्ली/भाषा। लुटियन्स दिल्ली में एक बौद्ध संगठन के सदस्यों ने शुक्रवार को मुगल और दिल्ली सल्तनत के शासकों के नाम पर सड़क के किनारे लगे साइनबोर्ड कथित तौर पर विरूपित कर दिए। भारतीय बौद्ध संघ के सदस्यों ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले साइनबोर्डों पर काले रंग का पेंट कर दिया। साइनबोर्ड में शाहजहां रोड पर 'वीर सावरकर मार्ग', तुगलक लेन पर 'अहिल्या बाई मार्ग', अकबर रोड पर 'महर्षि वाल्मीकि मार्ग', और हुमायूं रोड पर 'बालासाहेब ठाकरे मार्ग' लिख दिया गया। एनडीएमसी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी। भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष संचप्रिय राहुल ने 'पीटीआई वीडियो' से बातचीत के दौरान कहा, हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सार्वजनिक स्थानों से मुगल नामों को हटाने का आग्रह करते हैं, क्योंकि वे अत्याचारों के इतिहास का प्रतीक हैं। हमें ऐसे नामों की आवश्यकता नहीं है।

अमेरिकी जवाबी शुल्क का भारत पर कोई खास असर नहीं, उत्पन्न होंगे अवसर : नीति आयोग अधिकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक श्री साहू ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका की जवाबी शुल्क लगाने की योजना का भारत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे देश के लिए कई अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेक्सिको, चीन और कनाडा जिनकी अमेरिका के कुल आयात में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है उनकी तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक ने कहा, "हम आंकड़ों पर अलग-अलग स्तर पर गौर कर

रहे हैं... ये प्रारंभिक परिणाम हैं लेकिन में आपको केवल यह बता सकता हूँ कि हम नुकसान में नहीं रहेंगे। यह जवाबी शुल्क कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर किसी को प्रभावित नहीं करेगा और वास्तव में इसमें लाभ उठाने के कई अवसर हैं।"

साहू ने नीति आयोग की तिमाही व्यापार निगरानी के दूसरे संस्करण के पेश किए जाने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि जवाबी शुल्क योजना के भारत पर प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट के अगले संस्करण में पेश किया जाएगा। अमेरिकी बाजार में तीन मुख्य प्रतिस्पर्धी देश कनाडा, मेक्सिको और चीन हैं। अमेरिका के 3,100 अरब डॉलर के कुल आयात में इनकी 50 प्रतिशत

हिस्सेदारी है। इन देशों को 20-25 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, "इसलिए, यदि हम अपनी स्थिति की तुलना करें... अमेरिकी बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों पर इन शुल्क के लागू होने के बाद की स्थिति की तुलना करें तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। अमेरिका ने 12 मार्च से इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। उल्लेखनीय पूर्णतः निर्मित वाहनों (सीबीयू) और उसके कल-पुर्जों पर भी 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो तीन अर्थों से प्रभावी होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर अप्रैल से जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है।

त्योहारों के दौरान विमान किराये में बेतहाशा वृद्धि पर काबू के लिए सरकार कदम उठाये : वेणुगोपाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सदस्य के. सी. वेणुगोपाल ने त्योहारों के दौरान विमान किराये में बेतहाशा वृद्धि होने का मुद्दा उठाया और इस पर नियंत्रण के लिए सरकार से कदम उठाने की मांग की। वेणुगोपाल ने कहा, "उड़ानों के परिचालन पर हर तरह के शुल्क आम आदमी से वसूल किये जा रहे

हैं लेकिन इसे कौन घटायेगा। एटीएफ (विमान इंधन) पर शुल्क कौन घटाएगा? क्या यह आम आदमी की जिम्मेदारी है।" वह सदन में गैर-सरकारी कामकाज के तहत कांग्रेस सदस्य शफी परन्विल के 'देश में हवाई यात्रा किराये के विनियमन के लिए उचित उपाय' संबंधी निजी संकल्प पर हुई चर्चा में भाग ले रहे थे उन्होंने कहा, "मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि हम किराये में, विशेष रूप से त्योहारों के दौरान या आपात स्थिति



में यात्रा के लिए इस तरह की अत्यधिक वृद्धि को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं।" कांग्रेस सांसद ने कहा, "मैं समझ सकता हूँ कि विमान किराये का नियम मुश्किल

काम है। लेकिन त्योहारों के समय में विमान किराये में इस तरह की अत्यधिक वृद्धि की स्थिति में सरकार पूरी तरह से असहाय नजर आती है। यह कैसे चलेगा? यह सदन, माननीय मंत्री से इस बारे में जानना चाहता है।" उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि नागर विमान महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास शक्ति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास शुल्क नियमन की शक्ति है, बल्कि उसे निगरानी करने की शक्ति प्राप्त है। वेणुगोपाल ने सवाल किया,

"क्या ऐसा एक भी दृष्टांत है, जिसमें आपने सुव्यवस्थित प्रणाली का उल्लंघन करने वाली एयरलाइन को खिलाफ कार्रवाई की हो? डीजीसीए के पास सीमित शक्तियां हैं, लेकिन क्या उन सीमित शक्तियों के दायरे में वे कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं, मैं यह जानना चाहता हूँ।" उन्होंने विभिन्न हवाई अड्डों से परिचालित विमानों के किराये में अत्यधिक वृद्धि के विरोध में उदाहरण देते हुए कहा कि कोच्चि से सजदी अरब के जेटा तक के लिए विमान किराया 60,000 रुपए है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

फा.सं.17(20)/2021-पीएल/एनजीटी
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
नीति एवं विधि प्रभाग
एनजीटी प्रकॉड

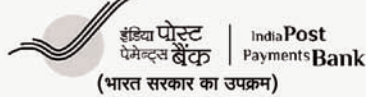
तृतीय तल, जल विंग,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग रोड, नई दिल्ली-03

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में न्यायिक सदस्य की दो (02) और विशेषज्ञ सदस्य की दो (02) संभावित रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

योग्यताएं, पद की शर्तें, आयु सीमा, सेवा संबंधी शर्तें आदि मंत्रालय की वेबसाइट www.moef.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र सहित विज्ञापन का विवरण वेबसाइट (<https://parivesh.nic.in/newupgradellegal-login>) पर उपलब्ध है।

मंत्रालय में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रकाशन की तिथि से चार सप्ताह अर्थात् दिनांक 25/04/2025 (23:59 बजे (मध्यरात्रि)) तक है। सभी आवेदन संलग्नकों सहित ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने हैं (<https://parivesh.nic.in/newupgradellegal-login>)। मंत्रालय आवेदन प्रस्तुत करने के किसी अन्य माध्यम पर विचार नहीं करेगा और न ही नियत दिनांक और समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई कार्रवाई करेगा।

CBC 13101/11/0025/2425



कोर्पोरेट कार्यालय, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

अनुबंध के आधार पर मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) और आंतरिक लोकपाल की भर्ती/रिक्तियों की भर्ती

विज्ञापन सं. : IPPB/CO/HR/RECT/2024-25/07

निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं

बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित संविदागत रिक्तियों की संख्या का विवरण (अंतिम तिथि):

विभाग	पद/पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	अनु. ज.	अनु. वन. ज.
अनुपालन	मुख्य अनुपालन अधिकारी	1	1	-	-
प्रचालन	मुख्य प्रचालन अधिकारी	1	-	-	1
आंतरिक लोकपाल	आंतरिक लोकपाल	1	1	-	-

भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों (न्यूनतम 40% दिव्यांगता) के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू है। महत्वपूर्ण तिथियाँ:

(i) आवेदन की ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि	29.03.2025 को प्रातः 10.00 बजे से
(ii) शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	18.04.2025 को रात 11.59 बजे तक

विस्तृत विज्ञापन के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट <https://ippbonline.com/web/ippb/current-openings> पर विजिट करें।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.03.2025
मुख्य मानव संसाधन अधिकारी
CBC 06346/12/0020/2425

सार्वजनिक नोटिस

न्यायमूर्ति बालाकृष्णन जांच आयोग

जबकि कुछ ऐसे व्यक्तियों के समूह, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक असमानता, अस्पृश्यता, भेदभाव और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न पिछड़ेपन को झेला है, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति घोषित किया गया है;

और जबकि, कुछ समूहों ने राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से अनुमत धर्मों से परे अन्य धर्मों से संबंधित न्यूनतम अनुसूचित जातियों का दर्जा देकर अनुसूचित जातियों की मौजूदा परिभाषा पर पुनर्विचार करने का प्रश्न उठाया है, और इसके विपरीत, कई अन्य समूहों ने भी इसका विरोध किया है;

और चूंकि, विद्यमान अनुसूचित जातियों के कुछ प्रतिनिधियों ने नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति की है; और चूंकि, यह एक मौलिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से जटिल समाजशास्त्रीय और संवैधानिक प्रश्न है, तथा सार्वजनिक महत्त्व का एक निश्चित मामला है;

और चूंकि, इसके महत्त्व, संवेदनशीलता और संभावित प्रभाव को देखते हुए, इस संबंध में परिभाषा में कोई भी परिवर्तन विस्तृत और निश्चित अध्ययन तथा सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर होना चाहिए और जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के तहत किसी आयोग ने अब तक इस मामले की जांच नहीं की है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4742(ई) दिनांक 06.10.2022 के तहत, जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है (<https://socialjustice.gov.in> पर उपलब्ध है) ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के तहत एक जांच आयोग नियुक्त किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, अर्थात्:

- I. अध्यक्ष - न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन, (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)
- II. सदस्य - श्री रवींद्र कुमार जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त) (एचपी-1981)
- III. सदस्य - प्रो. (डॉ.) सुषमा यादव, (पूर्व सदस्य, यूजीसी)

इसके बाद इसे 'न्यायमूर्ति बालाकृष्णन जांच आयोग' या 'आयोग' कहा जाएगा। इसका कार्यकाल राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4780(ई) दिनांक 30.10.2024 के तहत बढ़ा दिया गया है।

2. आयोग के विचारार्थ विषय:

- I. नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले की जांच करना, जो यह दावा करते हैं कि वे ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के थे, लेकिन उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्म के अलावा अन्य धर्म अपना लिया है;
- II. अनुसूचित जातियों की विद्यमान सूची के भाग के रूप में ऐसे नए व्यक्तियों को जोड़ने से विद्यमान अनुसूचित जातियों पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करना;
- III. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के रीति-रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक और अन्य स्थितिगत भेदभाव और वंचना के संदर्भ में अन्य धर्मों को अपनाने पर आने वाले परिवर्तनों की जांच करना, तथा उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के प्रश्न पर इसके निहितार्थ की जांच करना; और
- IV. आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी अन्य संबंधित प्रश्न की जांच केन्द्र सरकार के परामर्श और सहमति से करना।

3. इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विचारणीय विषयों (टीओआर) से संबंधित विषय की जानकारी रखने वाले तथा आयोग के समक्ष कार्यवाही में रुचि रखने वाले या आयोग की सहायता करने के इच्छुक सभी व्यक्ति, अपने तथ्यों का विवरण, प्रस्तुतियां या कोई अन्य प्रासंगिक साक्ष्य/विवरण आयोग को प्रस्तुत करें। प्रत्येक व्यक्ति तथ्यों, प्रस्तुतीकरण आदि का विवरण प्रस्तुत करते समय आयोग को वे दस्तावेज भी, यदि कोई हों, जिन्हें वह आयोग को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता है, प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने केरल, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान पहले ही प्रस्तुतीकरण दे दिया है तो उन्हें अतिरिक्त सूचना साझा करने के मामले को छोड़कर प्रस्तुतीकरण को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तथ्यों का विवरण, प्रस्तुतियां, दस्तावेज और अन्य विवरण आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय, तीसरी मंजिल, डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), 15 जनपथ, नई दिल्ली-110001 को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से या डिजिटली रसीद विकल्प के बाद पंजीकृत/स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। तथ्यों, प्रस्तुतीकरण, सहायक दस्तावेजों या किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री/विवरण के स्कैन किए गए और हस्ताक्षरित विवरण भी jbcommission-sje@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

न्यायमूर्ति बालाकृष्णन जांच आयोग
डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र
15 जनपथ, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29.3.2025
स्थान: नई दिल्ली

CBC 38101/11/0027/2425

‘कर्नाटक में चल रहा महंगाई का उत्सव’

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सरकार को घेरा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूरु। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने शुक्रवार को दूध की कीमतों में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।

भाजपा नेता का कहना है कि पिछले 20 महीनों में तीसरी बार दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दूध के दाम में कुल 9 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। आर अशोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दूध की कीमतों में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर कहा कि मैंने बजट सत्र में पहले ही कहा था कि विकास कार्यों के लिए टैक्स लगाना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सिद्धार्थमय्या ने चाल चली, उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया, बल्कि कीमतों में बढ़ोतरी की। पिछले 20 महीनों में यह तीसरी बढ़ोतरी है, दूध की कीमतों में कुल 9 रुपये बढ़ोतरी हुई है। गुणेश उरुवत के दौरान आपको एक और बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। महंगाई का उत्सव चल रहा है, जैसे विमान उड़ान के लिए कतार में खड़े हैं, वैसे ही यहां महंगाई का उत्सव चल रहा है।



आर अशोक ने कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने शुक्रवार को दूध की कीमतों में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।

आर अशोक ने कहा कि यह भी सीएम सिद्धार्थमय्या की चाल है, वह आंतरिक आरक्षण नहीं करते, वास्तव में हमारी सरकार पहले ही ऐसा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला दे दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे मंजूरी दे दी है, फिर भी वह ऐसा कर रहे हैं।

बांदीपुर वन (कांग्रेस सरकार शांम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का प्रतिबंध हटाना चाहती है) पर भाजपा नेता ने कहा कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मौजूद है, यह गैरकानूनी है। वे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं। उनके लिए वे लोग महान हैं।

अदालत का सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती ना करने का आदेश

बंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केनरा बैंक को निर्देश दिया है कि वह किसी सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी से बकाया ऋण वसूली के लिए उसकी पेंशन में से 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती न करे। अदालत ने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा का काम करती है और इसे धोखाधड़ी, जालसाजी या कदाचार के मामलों को छोड़कर पूरी तरह से ऋण चुकाने में नहीं लगाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस जी पंडित ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंकों को बकाया राशि वसूलने का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्हें पेंशनभोगियों की आजीविका की सुरक्षा करने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी की वित्तीय स्थिरता आवश्यक है और उन्हें ऋण चुकाने के लिए अपनी पूरी पेंशन छोड़ने के लिए मजबूर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। यह मामला अदालत के समक्ष 70 वर्षीय मुरुगन ओ के द्वारा लाया गया, जो केनरा बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं तथा वर्तमान में केरल के त्रिशूर में रहते हैं। मुरुगन 30 नवंबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए थे और अपनी पेंशन के एक हिस्से से लगातार अपने लोन की ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं। हालांकि, जुलाई 2024 से, केनरा बैंक ने बकाया चुकाने के लिए उनकी पूरी पेंशन काटनी शुरू कर दी, जिसके कारण उन्हें कानूनी हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी।

बंगलूरु में महिला की हत्या मामले में पति मुख्य संदिग्ध : पुलिस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूरु। कर्नाटक के बंगलूरु में 32 वर्षीय महिला का शव एक सूटकेस में मिलने के मामले में उसका पति मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला के पति ने कथित तौर पर आत्महत्या करने का प्रयास किया जिसका अब पुणे में इलाज हो रहा है। मृतक गौरी खेडकर का शव बृहस्पतिवार को एक सूटकेस में मिला था। वह महाराष्ट्र की मूल निवासी हैं।

पुलिस ने बताया कि उसका पति राकेश राजेंद्र खेडकर अपराध के बाद पुणे भाग गया, जहां उसने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मुख्य संदिग्ध राकेश राजेंद्र खेडकर को हत्या के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है और फिलहाल महाराष्ट्र के एक अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहर के पुलिस आयुक्त वी दयानंद ने कहा कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और ऐसा लगता है कि महिला का पति ही मुख्य संदिग्ध है। उन्होंने बताया, उसे पुणे के एक अस्पताल में भर्ती पाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या के प्रयास में जहर खा लिया था। वह अस्पताल में हैं और हमारी टीम

ने पुणे पुलिस से संपर्क किया है। दयानंद के अनुसार बंगलूरु पुलिस की एक टीम पुणे गई है और जैसे ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिलेगी उसे पूछताछ के लिए यहां लाया जाएगा। हत्या के पीछे वैवाहिक विवाद को कारण बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, मृतका के रिश्तेदार बंगलूरु आ गए हैं और बाकी जानकारी उनसे ली जाएगी। इससे पहले, बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे मकान मालिक ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी थी।

महिला और उसका पति पिछले महीने बंगलूरु चले गए थे और डोड्डाकम्मनहल्ली गांव में एक फ्लैट में रह रहे थे। महिला का पति एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करता है। महिला का शव फ्लैट के 'रूफटॉप' में सूटकेस में मिला। उसके शरीर पर चाकू के घाव के निशान थे।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी को यहां लाकर पूछताछ करने के बाद ही हत्या के पीछे के वास्तविक मकसद का पता चल सकेगा। अधिकारी ने कहा, मामले की जांच की जा रही है और इन विवरणों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। पुलिस ने बताया कि महिला के पति घर से काम करता था। पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किये हैं।

चित्रदुर्ग बेल्लारी आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उद्यम के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
दक्षिणी क्षेत्र-11 आरएचवयू, आरटीओ इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रेड टैक के पास, सिंगनायकनहल्ली,
येलहंका होबली, बंगलूरु-64. फोन 080-23093700

सार्वजनिक अधिसूचना

चित्रदुर्ग बेल्लारी आरईजेड ट्रांसमिशन लिमिटेड (जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत-110016 में है), भारत सरकार को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत सभी अधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन करना चाहता है ताकि विजली परेषण के लिए विद्युत लाइनों या विद्युत संयंत्र लगाए जा सकें या टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास जो सरकार द्वारा स्थापित या अनुमति किए जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए टेलीग्राफ लाइनों और पोस्ट लगाए जाने के संबंध में टेलीफोन या टेलीग्राफिक संयंत्र के प्रयोजन के लिए कार्यों के उचित समन्वय के लिए पुरस्कार अधिनियम, 2023 (पहले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885) के अंतर्गत आवश्यक हो और निम्नलिखित ट्रांसमिशन योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण, संस्थापन और अन्य कार्यों के बाद कमीशनिंग, परिचालन, रखरखाव और अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।
ट्रांसमिशन स्कीम का नाम: कर्नाटक में दावणगेरे/चित्रदुर्ग और बेल्लारी आरईजेड के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन स्कीम।
इस योजना के अंतर्गत शामिल कार्य:

क्र.सं.	ट्रांसमिशन स्कीम का कार्य क्षेत्र
1.	दावणगेरे/चित्रदुर्ग, कर्नाटक के पास 765/400 केवी 4X1500 एमवीए, 400/200 केवी 4X500 एमवीए पुलिंग स्टेशन की स्थापना जिसमें 400 केवी लेवल पर प्रत्येक 4500 एमवीए के दो (2) सेक्शन और 220 केवी लेवल पर प्रत्येक 2500 एमवीए के चार (4) सेक्शन का प्रावधान है।
2.	दावणगेरे/चित्रदुर्ग 765/400 केवी पीएस (40 किमी) पर नरेंद्र न्यू-मुगुगिरी 765 केवी डी/सी लाइन का एलआईएलओ (नरेंद्र न्यू-दावणगेरे खंड (-280 किमी) पर दोनों छोर पर 240 एमवीए/एर एसएलआर और दावणगेरे-मुगुगिरी खंड (200 किमी) पर दावणगेरे छोर पर 330 एमवीए/एर एसएलआर के साथ।
3.	दावणगेरे/चित्रदुर्ग पीएस में 2X330एमवीए/एर (765केवी) बस रिप्लेस
4.	नरेंद्र न्यू-मुगुगिरी 765 केवी डी/सी लाइन (वर्तमान में 400 केवी लेवल पर चाली) का उसके रेटेड 765 केवी वोल्टेज लेवल पर उन्नयन
5.	मुगुगिरी (वसंतरासापुर) को 3X1500 एमवीए, 765/400केवी आईसीटी और 2X330एमवीए/एर, 765केवी बस रिप्लेस के साथ 765 केवी लेवल के रेटेड वोल्टेज तक उन्नयन
6.	बेल्लारी क्षेत्र (बेल्लारी पीएस), कर्नाटक के निकट 4X500एमवीए, 400/220केवी पुलिंग स्टेशन की स्थापना
7.	बेल्लारी पीएस-दावणगेरे/चित्रदुर्ग 400 केवी (क्वाड एसीएसआर मूस) डी/सी लाइन
8.	बेल्लारी पीएस में 2X125 एमवीए 420केवी बस रिप्लेस

स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए नरेंद्र न्यू-मुगुगिरी पर नरेंद्र न्यू-मुगुगिरी 765 केवी डी/सी लाइन का उक्त टर्मिनेशन निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, आसपास और उनके बीच से होकर गुजरेगा:
राज्य: कर्नाटक

गांव का नाम	तालुक	जिला
मुगुगिरी	बसावनबागोडी (बसावनबागोडी)	बीजापुर (विजयपुर)
कुडगी (कुडगी), कुडगी तांडा	कोल्हार (कोल्हारा) (निगमगुडी)	बीजापुर (विजयपुर)

स्कीम के अंतर्गत मुगुगिरी स्टेशन पर नरेंद्र न्यू-मुगुगिरी 765 केवी डी/सी लाइन का उक्त टर्मिनेशन निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, चारों ओर और उनके बीच से होकर गुजरेगा:
राज्य: कर्नाटक

गांव का नाम	तालुक	जिला
येल्लाडल (येल्लाडल) [यालाडल], (गार्गेहल्ली), बच्चंद्र [बच्चंद्र], गिरिगंजहल्ली, सिंगनाहल्ली (सिंगनाहल्ली), गोल्डहल्ली [पी/टी गोल्डहल्ली], सिमराजहल्ली (सिमराजहल्ली), (कुट्टिकेम्पहल्ली), नागाजुहल्ली (नागाजुहल्ली), (यड्डहल्ली) [यड्डहल्ली], बोम्महल्ली, चिक्काहल्ली (चिक्काहल्ली) [चिक्काहल्ली], (वसंतरासापुर) [वसंतरासापुर], कोय्याडोडी, कोय्याडोडी, बुदुवण्ड (बुदुवण्ड) [बुदुवण्ड], शिवाडोडी, हुनगंतपुर, कर्तेहल्ली, गोल्लरहल्ली [गोल्लरहल्ली], (गौडीहल्ली)	तुमकूर (तुमकूर)	तुमकूर (तुमकूर)

स्कीम के अंतर्गत शामिल नरेंद्र न्यू-मुगुगिरी 765 केवी डी/सी लाइन दावणगेरे/चित्रदुर्ग 765/400 केवी पीएस (लाइन इन) का उक्त एलआईएलओ निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, उनके आसपास और उनके बीच से गुजरेगा:
राज्य: कर्नाटक

गांव का नाम	तालुक	जिला
जुम्नोहनहल्ली, लोकिरे, पुजारीहल्ली (पुजारीहल्ली), हुलिकेरे [हुलिकेरी], अलूर (अलूर), कुडलिंगी	कुडलिंगी	बेल्लारी (बेल्लारी) [विजयनगर]
कल्लहल्ली, केयमल्लहल्ली (केयमल्लहल्ली), कनमडुगु, सकलापुर	-	बेल्लारी (बेल्लारी) [विजयनगर]
पिचराहल्ली, यमलली, कन्नाबोरानाहल्ली, तंडाहल्ली	-	बेल्लारी (बेल्लारी) [विजयनगर]

गांव का नाम	तालुक	जिला
मुगुगिरीहल्ली [मुगुगिरीहल्ली], मद्रुनेहल्ली (मद्रुनेहल्ली), येरहल्ली [येरहल्ली], थारियेट (थारियेट) [थारियेट], कानकट्टे, हुच्चयहल्ली (हुच्चयहल्ली) [हुच्चयहल्ली], बंगारानगुड्डा, हिरे मल्लानाहोळे (हिरेमल्लानाहोळे) [हिरेमल्लानाहोळे], बदादनहल्ली, भरमासमुद्र (भरमासमुद्र), सिद्धमहल्ली, कामागेथनहल्ली (कामागेथनहल्ली), मुदलमाचिकेरे (मुदलमाचिकेरे), तिम्मलापुर (तिम्मलापुर) [तिम्मलापुर], गोमुड्ड, (रैडीहल्ली), हुनगंतपुर (हुनगंतपुर), रंगपुर, उड्डाण्ड (उड्डाण्ड), जगलूर (जगलूर) [टीपी]/ग्रामीण, पापेवराहल्ली, चिक्काहल्ली (चिक्काहल्ली), कनक्युपा (कनक्युपा), गिदिकण्ड (गिदिकण्ड), बायरीकहल्ली (बायरीकहल्ली), केलागोटे (केलागोटे), केथेनहल्ली (केथेनहल्ली), वीरयनगतिहल्ली (वीरयनगतिहल्ली), गोडगांझानहल्ली (गोडगांझानहल्ली) [गोडगांझानहल्ली], तमाडिहल्ली (तमाडिहल्ली) [तमाडिहल्ली], बग्गेनहल्ली, रस्से माचिकेरे (रस्सेमाचिकेरे), मालमहल्ली, बुल्लानहल्ली, कस्तुरीपुर, व्यासगोडानहल्ली (व्यासगोडानहल्ली) [व्यासगोडानहल्ली], गोपागोडानहल्ली, विरुवल्ल, बिदारकेरे (बिदारकेरे), निवागूर (निवागूर) [निवागूर], सते मुगुगुर (सतेमुगुगुर) [सतेमुगुगुर], मुगुगुर, सोमनहल्ली, रस्से मडुटे (रस्सेमडुटे), कट्टिकेम्पहल्ली, कोरटिकेरे (कोरटिकेरे), इलावडी, देवीकेरे, महारासनाहल्ली, अरसिनागुडी [अरसिनागुडी], जन्मपुर, सिंगनाहल्ली, बोम्महल्ली, मारेनहल्ली, मदागिनकेरे (मदागिनकेरे), सेट्टीगोडानहल्ली (सेट्टीगोडानहल्ली), चन्नापुर, बसवपुर, कोटादागुड्डा [कोटादागुड्डा], मुसिगंजहल्ली, हुच्चयहल्ली (हुच्चयहल्ली) [हुच्चयहल्ली], कसावहल्ली, महाराजहल्ली, राजेनहल्ली, अय्यनहल्ली, ब्याटगरनहल्ली (ब्याटगरनहल्ली), होन्नामरडी [होन्नामरडी], दोनेहल्ली (दोनेहल्ली), मुसुगुर (मुसुगुर), बेन्नेहल्ली, कुलोमनहल्ली, लक्कनहल्ली, अनाबेनकनहल्ली, विरागोडानहल्ली, कोरसरहल्ली, अकनकूर	जगलूर (जगलूर)	दावणगेरे
बड्डरहल्ली [बड्डरहल्ली]	होन्नाली	दावणगेरे
गोल्लरहल्ली, लम्बानिहल्ली, अनाबुकर (अनाबुकर) [अनाबुकर], गोल्लरहल्ली	दावणगेरे	दावणगेरे
मालु	-	दावणगेरे

स्कीम के अंतर्गत शामिल नरेंद्र न्यू-मुगुगिरी 765 केवी डी/सी लाइन दावणगेरे/चित्रदुर्ग 765/400 केवी पीएस (लाइन आउट) का उक्त एलआईएलओ निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, उनके आसपास और उनके बीच से गुजरेगा:
राज्य: कर्नाटक

गांव का नाम	तालुक	जिला
जुम्नोहनहल्ली, लोकिरे, पुजारीहल्ली (पुजारीहल्ली), हुलिकेरे [हुलिकेरी], अलूर (अलूर), कुडलिंगी	कुडलिंगी	बेल्लारी (बेल्लारी) [विजयनगर]
कल्लहल्ली, केयमल्लहल्ली (केयमल्लहल्ली), कनमडुगु, सकलापुर	-	बेल्लारी (बेल्लारी) [विजयनगर]
पिचराहल्ली, यमलली, कन्नाबोरानाहल्ली, तंडाहल्ली	-	बेल्लारी (बेल्लारी) [विजयनगर]

गांव का नाम	तालुक	जिला
मुगुगिरीहल्ली [मुगुगिरीहल्ली], मद्रुनेहल्ली (मद्रुनेहल्ली), येरहल्ली [येरहल्ली], थारियेट (थारियेट) [थारियेट], कानकट्टे, हुच्चयहल्ली (हुच्चयहल्ली) [हुच्चयहल्ली], बंगारानगुड्डा, हिरे मल्लानाहोळे (हिरेमल्लानाहोळे) [हिरेमल्लानाहोळे], बदादनहल्ली, भरमासमुद्र (भरमासमुद्र), सिद्धमहल्ली, कामागेथनहल्ली (कामागेथनहल्ली), मुदलमाचिकेरे (मुदलमाचिकेरे), तिम्मलापुर (तिम्मलापुर) [तिम्मलापुर], गोमुड्ड, (रैडीहल्ली), हुनगंतपुर (हुनगंतपुर), रंगपुर, उड्डाण्ड (उड्डाण्ड), जगलूर (जगलूर) [टीपी]/ग्रामीण, पापेवराहल्ली, चिक्काहल्ली (चिक्काहल्ली), कनक्युपा (कनक्युपा), गिदिकण्ड (गिदिकण्ड), बायरीकहल्ली (बायरीकहल्ली), केलागोटे (केलागोटे), केथेनहल्ली (केथेनहल्ली), वीरयनगतिहल्ली (वीरयनगतिहल्ली), गोडगांझानहल्ली (गोडगांझ		

राजस्थानी पोशाक पहनकर विद्यालय आएंगे शिक्षक-विद्यार्थी, नमस्ते-गुड मॉर्निंग की जगह बोलेंगे खम्माघणी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, 30 मार्च 2025 को रविवार होने के कारण राजकीय विद्यालयों में 29 मार्च को ही राजस्थान दिवस के अवसर पर नो बैंग डे के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किये हैं। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। जिसके तहत राजस्थान दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को राजस्थानी भाषा एवं

संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए विद्यार्थी, शिक्षक सहित विद्यालय के अन्य कर्मचारी साफा, धोती-कुर्ता, कुर्ता-पायजामा, राजपूती पोशाक जैसी पारंपरिक पोशाक पहनकर आएंगे। इससे विद्यार्थियों को राज्य की लोक परंपराओं से जुड़ने एवं सांस्कृतिक विविधता को करीब से समझने एवं आत्मसात करने का अवसर मिलेगा।

वहीं, राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी अभिवादन में गुड मॉर्निंग या नमस्ते के स्थान पर खम्मा घणी, राम-राम सा, पधारो सा बोलेंगे। राजस्थानी भाषा में भाषण, कविता प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, राजस्थानी शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों से परिचय करवाया जाएगा



राजस्थान पर्यटन विभाग को तीन श्रेणी में मिले पुरस्कार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दीपा कुमारी की ओर से राजस्थान पर्यटन को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। इसी का सुपरिणाम है कि इंडिया टुडे समूह द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग को तीन श्रेणी में इंडिया टुडे ट्रैवल्स अवार्ड्स 2025 प्रदान किए गए। राजस्थान पर्यटन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने उक्त पुरस्कार ग्रहण किए।

उल्लेखनीय है कि इंडिया टुडे ट्रैवल्स सर्वे और अवार्ड्स समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जिसमें देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के तरीकों पर गहन सत्रों के आयोजन के अलावा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को वार्षिक पर्यटन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।



भजनलाल ने दस हजार करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भीलवाड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सुशासन का मंत्र बताते हुए कहा है कि विकास और सुशासन के इस संकल्प में जनता का साथ हमारी ताकत है और हम राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। शर्मा शुक्रवार को भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित विकास एवं सुशासन उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान के एकीकरण में अपना अमूल्य योगदान देने वाली महान विभूतियों को, विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब से हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही 10 हजार करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने नगरीय विकास विभाग से संबंधित

डेलीगेशन के आदेश, फायर एनऑसि प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, नए जिलों में डीएनएफटी के गठन, हरित अरावली विकास परियोजना, अन्नपूर्णा भण्डार, रजिस्ट्रार कार्यालय सप्ताह में दो दिन सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक खुलने के दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर सभी जिलों की पंचगौरव पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इससे स्थानीय क्षमताओं और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के प्रहरी और चौथा स्तंभ हैं। विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में उनकी भूमिका अहम है। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने पत्रकार हेल्थ कवरज (आरजेएफएस) योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया है। इससे मरीज घर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के आज जारी हुए दिशा-निर्देश शहरों को और अधिक समृद्ध और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के शासन में महिला उत्पीड़न, पेपर लीक रूपों के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने नगरीय विकास विभाग से संबंधित



जैसे मामलों से प्रदेश अराजकता और अस्थिरता की गिरफ्त में रहा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में केवल जनता को दिखाने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट का किया था जबकि हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में राजिग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, क्योंकि हमारी मंशा इन एमओयू को धरातल पर उतारना है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। हमारी सरकार किसान, युवा, मजदूर, महिला के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमने किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने का लक्ष्य

रखा है, साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न नीतियां जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में 12 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल, पेपर लीक प्रकरणों में गिरफ्तारी, राजिग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू, राम जल सेतु लिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते जैसे जनता से किए गए प्रत्येक वादे को पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। इसी के मद्देनजर हमारी सरकार आमजन की बेहतरी और कल्याण के लिए काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ आलोक रंजन, जिला कलक्टर डूंगरपुर अमित कुमार सिंह, शासन सचिव कार्मिक के.के. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाबी ने कहा कि 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समातन संस्कृति की परंपरा को कायम करते हुए हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाए जाने की सराहनीय पहल की है। उन्होंने कहा कि सुशासन लोकतंत्र की रीढ़ है और अच्छी नीति एवं नीयत के साथ ही सुशासन स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए राजिग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अन्तर्गत 35 लाख करोड़ के निवेश एमओयू हुए हैं, जिससे

प्रदेश विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे।

उपमुख्यमंत्री डा प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है। मुख्यमंत्री की पहल पर साप्ताहिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान दिवस का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत विभिन्न वर्गों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के भगीरथ प्रयासों से उबल उठने की सरकार प्रदेश में प्रगति के पथ पर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ आलोक रंजन, जिला कलक्टर डूंगरपुर अमित कुमार सिंह, शासन सचिव कार्मिक के.के. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाबी ने कहा कि 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समातन संस्कृति की परंपरा को कायम करते हुए हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाए जाने की सराहनीय पहल की है। उन्होंने कहा कि सुशासन लोकतंत्र की रीढ़ है और अच्छी नीति एवं नीयत के साथ ही सुशासन स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए राजिग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अन्तर्गत 35 लाख करोड़ के निवेश एमओयू हुए हैं, जिससे



प्रवासी राजस्थानी समुदाय ने राजस्थान की कला और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गौरवान्वित : राठौड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की कला और संस्कृति विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। प्रवासी राजस्थानी समुदाय ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति और कारीगरों की अनूठी कला को संवर्धन और संरक्षण करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में साप्ताहिक महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान फाउंडेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित 28 से 30 मार्च तक तीन दिवसीय 'प्रवासी आर्ट प्रदर्शनी और क्रिएटिविटी वर्कशॉप' का शुभारंभ को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुभारंभ किया।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि यह प्रदर्शनी न केवल प्रवासियों के हृदय व कला के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करने का एक मंच है, बल्कि यह प्रवासी राजस्थानियों और उनके गृह राज्य के बीच सांस्कृतिक सेतु को और अधिक मजबूत करने का भी अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है, इससे प्रवासी समुदाय का राज्य से जुड़ाव और अधिक प्रगाढ़ होगा। उन्होंने वर्कशॉप में जेंटिंगल्स आर्ट और वाटर कलर पेंटिंग सीख रहे प्रतिभागियों के साथ संवाद किया और वर्कशॉप में पारंपरिक खेलों बाघ-बकर, चार-भर और सोलह गुटियां, चतुरंग सेट, रज्जू सरपा, निर्यानवाय का फेर आदि पर भी हाथ आजमाया।

इस दौरान कर्नल राठौड़ ने जवाहर कला केंद्र में ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) द्वारा आयोजित शिल्पान्गन प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का अवलोकन कर हस्तशिल्पियों से संवाद किया। शिल्पान्गन में टेक्सटाइल व मिनिचर पेंटिंग, लकड़ी, पत्थर व संगमरमर हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित

कृतियां और आभूषण के साथ-साथ चर्म उत्पाद, मोजड़ी, जयपुर ब्लू पॉटरी को प्रदर्शित किया गया। राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ मनीषा अरोड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से 5 देशों और 8 राज्यों के प्रतिभाशाली प्रवासी राजस्थानियों की कलाकृतियों को पहली बार एक साथ लाया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के रत्नसम, चूरी से कोलकाता में बसे प्रवासी राजस्थानी अमन गोपाल पिछले कई वर्षों से पारंपरिक रॉयल बोर्ड गेम्स को पुनर्जीवित एवं प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। डॉ. अरोड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में देश-विदेश के प्रवासी राजस्थानियों की कलात्मक प्रतिभा को एक मंच प्रदान किया गया है जिसमें पारंपरिक शाही बोर्ड गेम्स, जेंटिंगल्स, आकर्षक कशीदाकारी, पेंटिंग्स और स्करपचर्स जैसी विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही, क्रिएटिविटी वर्कशॉप में युवाओं को जेंटिंगल्स आर्ट, वाटर कलर पेंटिंग और पारंपरिक रॉयल बोर्ड गेम्स के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।



माल्टा में पहली बार गुंजेगा 'पधारो म्हारे देश', दौसा की धोली मीणा की अनूठी पहल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दौसा। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की गुंज अब यूरोप तक पहुंच चुकी है। पहली बार, 30 मार्च को यूरोप के माल्टा में भव्य राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की अगुवाई दौसा की धोली मीणा कर रही हैं, जो वर्षों से भारतीय और राजस्थानी संस्कृति के प्रचार-प्रसार में जुटी हुई हैं।

राजस्थान दिवस पर राजधानी वैंलेटा में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, भव्य परेड, प्रदर्शनीयां और उत्सव आयोजित किए जाएंगे। भारतीय दूतावास और राजस्थानी समुदाय के सहयोग से होने वाले इस आयोजन में न केवल राजस्थान के प्रवासी, बल्कि माल्टा और अन्य देशों के गणमान्य लोग भी भाग लेंगे। हॉलीवुड और ब्यूटी क्रीस की रहेगी मौजूदगी : धोली मीणा ने बताया कि इस खास आयोजन में प्रतिष्ठित मेहमान भी शामिल होंगे, जिनमें मिस वर्ल्ड माल्टा मिस माट्टिनो काटजर, जो इस साल हैदराबाद में होने वाली मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में माल्टा का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस यूनिवर्स माल्टा विजेता वीट्रिक नजोया। हॉलीवुड एक्टर डेविड टुषी। धोली मीणा ने बताया कि उन्होंने 20 से अधिक महिलाओं की टीम बनाकर राजस्थानी लोकनृत्य का प्रस्तुति के लिए विशेष तैयारी की है। मेहमानों के लिए दाल-बाटी-चूरमा सहित पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था। मेहंदी स्टॉल, राजस्थानी परिधानों की प्रदर्शनी और खास फोटो बुथ, जहां यूरोपियन मेहमान राजस्थानी वेशभूषा में तस्वीरें ले सकेंगे। भारत-माल्टा के कूटनीतिक रिश्तों की 60वीं वर्षगांठइस आयोजन का एक और ऐतिहासिक महत्व यह है कि 10 मार्च 2025 को भारत और माल्टा के कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर यह समारोह दोनों देशों की सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। धोली मीणा की इस पहल से राजस्थान की संस्कृति को वैश्विक मंच मिल रहा है, जो हर प्रवासी राजस्थानी के लिए गर्व की बात है।



राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास के नए प्रतिमान किए स्थापित : जोगाराम पटेल

जयपुर, । राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन अकादमी के भगवत सिंह मेहता सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव का आयोजन हुआ। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किये हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार ने डेढ़ साल से भी कम समय में जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हमारी गौरवशाली परंपरा एवं संस्कृति को एक बार फिर से अपना यथोचित सम्मान दिलाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि 30 मार्च 1949 को चार बड़ी रियासतों का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया था। वृहद राजस्थान के गठन उपलक्ष्य में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, यह भारतीय नवयव की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को खेती नक्षत्र इंद्रयोग की शुभ घड़ी में अस्तित्व में आया था। सौभाग्य से इस बार भी वही शुभ संयोग बन रहा है। इस साल से मुख्यमंत्री जी ने अब से हिन्दु नवयव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाने का अभूतपूर्व एवं लोकप्रिय फैसला किया है।

वहीं, नगर निगम जयपुर हैरिटेज की महापौर कुसुम यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की तस्वीर में विकास के रंग भरने का काम कर रही है। सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों से हर तबके, हर वर्ग को राहत पहुंची है।

भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया, जिला स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद किसानों और जनप्रतिनिधियों ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा। सुशासन समारोह में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर जिले के पंच गौरव पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया एवं राजकीय योजनाओं के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कार्मिकों को सम्मानित किया गया। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लाभार्थियों को योजना के तहत अंतिम किश्त का चेक भी साँपा गया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त पूनम, जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज के आयुक्त अरुण कुमार हीराजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर युकेश कुमार मूंड के साथ-साथ नगरीय विकास विभाग, सांख्यिकी विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों, लाभार्थियों ने शिरकत की।

राजस्थान सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध : शर्मा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वृहदस्तरिताय को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी जेलों को मजबूत एवं आधुनिक बनाने के लिए जेल विभाग को आवश्यकता अनुरूप सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

यह बैठक जयपुर केन्द्रीय कारागार में बंद बदमाशों द्वारा उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद आयोजित की गई। इस मामले में पुलिस से तीन लोगों को हिरासत में लिया है। शर्मा ने जेल विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि जेल परिसर में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश की सभी जेलों में पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित एवं औचक तलाशी अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि जेलों में अवांछित सामग्री मिलने पर संबंधित जेल प्रशासन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

